भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3291
गुरुवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति, 2008

3291. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में और विशेषकर धुले लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन नीति, 2008 के अंतर्गत स्वीकृत ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थिति क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का कार्बन-न्यूट्रल टर्मिनलों जैसे संधारणीय विकास मानकों को शामिल करने के लिए उक्त नीति में कोई संशोधन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में चल रही विमानपत्तन विकास परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन का संवर्धन करने और संपर्क में सुधार के लिए धाराशिव (उस्मानाबाद) को उड़ान योजना में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देशभर में तीन अर्थात तमिलनाडु में परंदुर, ओडिशा में पुरी और राजस्थान में कोटा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति के तहत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया गया है। नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) को धुले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण हेतु जीएफए नीति के तहत अनुमोदन की माँग करने वाला कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाएं लंबी जेस्टेशन पीरियड के साथ पूँजी परक होती हैं और हवाईअड्डा परियोजनाओं को पूर्ण करने की समय-सीमा भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है।

(ख) : नागर विमानन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के विकासकर्ताओं को कार्बन न्यूट्रैलिटी और नेट जीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है।

(ग) : हवाईअड्डा अवसंरचना का विस्तार और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और अन्य हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा समय-समय पर भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक सरोकारों, यातायात माँग और ऐसे हवाईअड्डों से/हवाईअड्डों के लिए परिचालन करने हेतु एयरलाइनों की इच्छा के आधार पर निष्पादित की जाती है। महाराष्ट्र राज्य में एएआई ने पुणे हवाईअड्डे पर पुराने टर्मिनल भवन के

पुनर्निर्माण और जुहू हवाईअड्डे पर रनवे की रिसर्फेसिंग का कार्य शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) ने शिरडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण और संबंधित अवसंरचना का कार्य और आरसीएस-'उड़ान' योजना के तहत रत्नागिरी हवाईअड्डे का विकास कार्य भी शुरू किया है।

(घ) : उस्मानाबाद हवाईपट्टी 'उड़ान' योजना दस्तावेज में असेवित हवाईपट्टियों/हवाईअड्डों की संभावित सूची में उपलब्ध है। 'उड़ान' योजना के तहत बोली प्रक्रिया के 5 चरण पूर्ण होने तक उस्मानाबाद के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है। यदि भविष्य में इस हवाईपट्टी को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ानों के परिचालन हेतु कोई वैध बोली प्राप्त होती है, तो इस पर 'उड़ान' योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

*****